



## बिहार राज्य के एमएसएमई विकास में स्टार्टअप की भूमिका का अध्ययन ।

डॉ० कौसर अली, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग  
कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, बिहार ।

**शोध सारांश**— बिहार भारत का एक अति पिछड़ा राज्य है, यहाँ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं। बिहार में लगभग आधी आबादी युवा है। राज्य के युवाओं में प्रतिभा, दूरदर्शिता के साथ उद्यमिता की कमी नहीं है। भविष्य में बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रगति इन्हीं युवा उद्यमियों पर निर्भर करेगी। ऐसे में बिहार सरकार की पहल बिहार स्टार्टअप नीति 2016 युवाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र में सुनहरा अवसर प्रदान कर सकती है।

स्टार्टअप कार्यक्रम बिहार की आर्थिक विकास का इंजन है। यह कार्यक्रम युवाओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में उद्यमिता एवं नवचार हेतु प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, आई० टी० जैसे क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। स्टार्टअप कार्यक्रम द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में इसकी अपार सम्भावनाएँ हैं। इससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। इस शोध पत्र के माध्यम से बिहार राज्य के एमएसएमई विकास में स्टार्टअप की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा।

**परिचय**— बिहार सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति 2016 लागू किया। इसका उद्देश्य राज्य में लघु, एवं कुटीर उद्योग का विकास तथा रोजगार सृजन करना है। यह नीति हस्तशिल्प, कपड़ा तथा कृषि आधारित उद्योग पर केन्द्रित है। इस नीति के अन्तर्गत युवा उद्यमियों को स्टार्टअप के माध्यम से 10 लाख रुपये तक 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों में निवेश करने वाले युवा उद्यमियों को आवश्यकतानुसार परामर्श, प्रशिक्षण एवं विपणन से सम्बंधित सहायता भी प्रदान की जाएगी। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2016 के स्थान पर 2022 को मंजूरी दी गई। इस नीति की संकल्पना राज्य में समावेशी विकास, अनुकूल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, युवा प्रतिभा का लाभ उठाना तथा उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाकर बिहार को स्टार्टअप हब बनाना है।

बिहार भारत का अति पिछड़ा राज्य है, यहाँ एमएसएमई एवं पूंजी का अभाव है। बिहार के पास कृषि योग्य भूमि एवं विशाल जनसंख्या है। राज्य के पिछड़ेपन के लिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ेपन, बुनियादी ढाँचा का अभाव एवं पूंजी निवेश की कमी जिम्मेदार है। राज्य में श्रम की बहुलता है। यहाँ से अधिकांश श्रमिक रोजगार के अभाव में पलायन कर जाते हैं। यद्यपि मौजूदा सरकार

आधारभूत संरचना यथा निर्बाध बिजली, सड़क, संचार सुदृढ़ करने में सफल रही है तथापि अपेक्षाकृत पूंजी निवेश आकारित करने में उतनी सफलता नहीं मिली है।

**साहित्य समीक्षा**— बिहार के एमएसएमई में स्टार्टअप की भूमिका का अध्ययन वर्तमान समय की मांग है। वर्तमान समय में बिहार जनसंख्या दबाव, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, तकनीकी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं, एमएसएमई की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में छोटे स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप एवं स्वरोजगार लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस विषय पर निम्नलिखित अध्ययन हुए हैं—

- ❖ **ए0 एम0 कादकोल एवं राजहुसैन नादफ** (भारत में एमएसएमई के विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर एक अध्ययन-2019) ने अध्ययन किया और पाया कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो देश की सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक, गरीबी को कम करने, रोजगार सृजित करने और ग्रामीण-शहरी प्रवास को हतोत्साहित करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। ये उद्यम सम्पन्न उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के साथ-साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देता है। भारत में एमएसएमई की समग्र विकास के लिए वित्तीय संस्थाएँ प्रशिक्षण एवं परामर्श सहायता कर रही है।
- ❖ **सुमीत मिश्रा** (भारत में स्टार्टअप-अवसर और चुनौतियाँ-2017) ने विषय पर अध्ययन किया और लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्टार्टअप में सामना की जाने वाली अवसरों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। एमएसएमई के स्टार्टअप द्वारा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन एवं बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है, परन्तु एक उद्यमी द्वारा अपने व्यवसाय को लाभ कमाने वाली एमएसएमई में बदलने के लिए अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ❖ **दीपक अधाना** (भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020) ने विषय पर अध्ययन किया और पाया कि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उपभोक्ता बाजार है, जहाँ एक तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आय तथा उपभोग तेजी से बढ़ रही है वही दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं आधारभूत संरचना पिछड़ी अवस्था में है। जबकि यह एमएसएमई स्टार्टअप के लिए उपयोगी है। स्टार्टअप के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान संभव है।

### अध्ययन का उद्देश्य –

1. बिहार के एमएसएमई विकास में स्टार्टअप की भूमिका का मूल्यांकन करना है।
2. बिहार स्टार्टअप योजना के बाद एमएसएमई की संभावनाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना है।

एमएसएमई के विकास में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। स्टार्टअप नवचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देता है। एमएसएमई की स्थापना से रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप को गति देने के लिए बिहार सरकार द्वारा दो योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (प्रारम्भ वर्ष-2018) के अन्तर्गत अब तक 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किये गए हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना (आरम्भ वर्ष 2023) के अन्तर्गत एमएसएमई की स्थापना एवं संचालन के लिए प्रत्येक लाभार्थी को दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त में 200 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं। राज्य में 255 स्टार्टअप को वर्ष 2023-24 में मान्यता दी गई। जिसमें सीड फंडिंग

के रूप में कुल 11.92 करोड़ रुपये वितरित किये गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 149 इकाइयों को बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा 3950.48 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बिहार सरकार एमएसएमई स्टार्टअप द्वारा समाज के वंचित वर्गों यथा पिछड़े एवं महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर उनके उत्थान हेतु विशेष बल दे रही है।

बिहार स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत एमएसएमई विकास की सम्भावनाओं के साथ-साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं। राज्य सरकार एमएसएमई को गति देने हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है।

### संभावनाएँ—

- ❖ बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसलिए कृषि आधारित स्टार्टअप जैसे खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, बागवानी, वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग के विस्तार की अपार सम्भावनाएँ हैं।
- ❖ डिजिटल स्टार्टअप जैसे ई-कामर्स, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में स्टार्टअप स्थापित किये जा सकते हैं।
- ❖ एमएसएमई स्टार्टअप के लिए कौशल विकास, उत्पादन एवं विपणन बढ़ाने तथा कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास सराहनीय होगा।
- ❖ एमएसएमई स्टार्टअप द्वारा रोजगार सृजन एवं निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- ❖ बिहार सरकार एमएसएमई को गति देने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार उद्यमी योजना चला रही है। इस योजना द्वारा लाभार्थियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

### चुनौतियाँ—

- ❖ बिहार स्टार्टअप के लिए पूंजी एवं तकनीक का अभाव, उत्पाद के विपणन में असुविधा, बुनियादी ढाँचे का अभाव, उद्यमियों की अकुशलता, एमएसएमई विकास में प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- ❖ एमएसएमई स्टार्टअप मुख्य रूप से स्थानीय एवं छोटे पैमाने के होते हैं, ऐसे में व्यापारिक गतिविधियों को दिशा देना एक बड़ी चुनौती है।

**निष्कर्ष—** एमएसएमई बिहार में स्टार्टअप हेतु एक मजबूत आधार है। इसके लिए सरकार “उद्यमी बिहार समृद्ध बिहार” नाम से कैम्पेन भी चला रही है। यद्यपि स्टार्टअप को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं तथापि बुनियादी ढाँचे का अभाव, अकुशलता एवं वित्त सम्बंधी समस्याएँ इसमें बाधा पहुँचा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, बुनियादी ढाँचे का विकास, वित्तीय सहायता एवं जागरूकता अभियान पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है।

## संदर्भ सूची –

1. Dr. Ch. Hema Venkata Sivasree, Dr. P. Vasavi, MSMES in India Growth and Challenges, Journal of Scientific Computing, ISSN No- 1524-2560, Volume-9, Issue 2, 2020
2. Pema Lama, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in India-Problems and Prospects, Business studies Vol: XXXIII & XXXIV, 2022 & 2023
3. Ajit Singh, MSMEs Sector in India : Current Status and Prospect, International Journal of Innovation Research in Engineering & Management Volume – 8, Issue – 4, July 2021
4. Sumit Mishra, Start up in India: Opportunities and Challenges, Jan, 2017.
5. Tripda Rawal, An inside view in Indian start-ups, International journal of creative research thoughts, Vol- 06, Issue- 01, Feb. 2018.
6. <https://udyami.bihar.gov.in>

